percent seats reserved for them.The year-wise split up is as under:—

Year	Number of children
1993-94	21
1994-95	10
1995-96	10

9. The Government of Punjab intends to continue to import training to the terrorist affected women and to grant employment under the exsiting schemes on priority basis during the next three years also.

Report on India by Trade Development Board, Singapore

845. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to certain reports which appeared on 20th June, 1996 indicating Singapore's Trade Development Board New Plan for India advocating a focus on regional growth areas, instead of concentrating all investment in one area or well established regions;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some initiatives in this regard for implementation of plan of Singapore;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) Although a report regarding Singapore's Trade Development Board New Plan for India has appeared in the Press, no official communication nor the details of such a Plan have been received trom the Singapore Trade Development Board.

© to (e) Do not arise.

सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्यालय

846. **श्री जनार्दन यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी-क्षेत्र के ऐसे अनेक उपक्रम हैं जिनकी उत्पादन इकाइयां तो देश के विभिन्न भागों में स्थापित हैं किन्तु उनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इन उपक्रमों के प्रशासनिक कार्य में सुधार करने हेतु उनके प्रशासनिक मुख्यालयों का उत्पादन इकाइयों के समीप स्थित होना आवश्यक नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1996 में इन कार्यालयों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था;

(ङ) कितने कार्यालयों को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है; और

(च) शेष कार्यालयों को स्थानांतरित न किये जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के 21 उत्पादनकारी/विनिर्माणकारी उद्यम ऐसे हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं जबकि उनके उत्पादनकारी एकक देश के विभिन्न भागों में अवस्थित हैं। इन उपक्रमों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। चूंकि इन उद्यमों के उत्पादन तथा प्रचलन संबंधी अन्य कार्यकलाप देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। इसलिए इनके द्वारा यह वांछनीय समझा गया है कि मुख्यालय ऐसे केन्द्रीय स्थल पर स्थित हों जहां से कारगर नियंत्रण संभव हो सके।

(घ) से (च) राजधानी के शहर को भीड़-भाड़ से मुक्त करने संबंधी उपाय के तौर पर सरकार ने वर्ष 1986 में, न कि 1996 में सरकारी क्षेत्र के कुछेक उन उपक्रमों का निर्धारण किया जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाना था। इनमें से चार उद्यमों ने अपना कार्यालय स्थानांतरित कर लिया है जबकि अन्य प्रशासनिक/प्रचालनात्मक कारणों से ऐसा नहीं कर सके है।